लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये चूरू ज़िला कलक्टर सम्मानित

चर्चा में क्यों?

21 अप्रैल, 2022 को सिविल सेवा दिवस पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू ज़िला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- 'खेलो इंडिया' अभियान के तहत ज़िले में हुए उत्कृष्ट कार्यों और बेहतर उपलब्धियों के लिये चूरू ज़िले को मिले इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने ज़िला कलक्टर को 20 लाख रुपए का चेक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
- यह पुरस्कार ज़िले में विकसित खेल केंद्रों, खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पदक, महिला खिलाड़ियों, पैरा-खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व, फिट इंडिया-खेलो इंडिया में ज़िला प्रशासन द्वारा किये गए नवाचार में युवा खिलाड़ियों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के लिये दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि ज़िले में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के द्वारा स्वीकृत खेलो इंडिया के 8 केंद्र एथलेटिक्स राजगढ़, द्रोणाचार्य राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी अकादमी राजगढ़, टेबल टेनिस ज़िला स्टेडियम चूरू, हॉकी गाजुवास, हैंडबॉल एकेडमी लोहा, भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाज़ी उर्मिला खेल अकादमी न्यांगल बड़ी संचालित हैं, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक हैं।
- ज़िला स्टेडियम चूरू में साई के 6.30 करोड़ से नवनिर्मित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन **(IAAF)** द्वारा प्रमाणित वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया गया है।
- गौरतलब है कि ज़िले के 34 खिलाड़ियों द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2019 और 2020 में प्रतिनिधित्व किया गया था। इनमें से 10 खिलाड़ियों द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2020 में पदक प्राप्त किये गए, जो राजस्थान को मिले पदकों का 20 प्रतिशत था।
- ज़िले में सन् 2019 से 2021 तक महिला एवं पैरा-खिलाड़ियों का खेल में अच्छा प्रतिनिधित्व रहा तथा महिला और पैरा-खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किये। ज़िला प्रशासन द्वारा नवाचार के रूप में ज़िले के विद्यालयों में पोषण और स्वास्थ्य जागरुकता अभियान चलाकर बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर फिट इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाया गया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/churu-district-collector-honored-for-excellence-in-public-administration